ज्ञानचंद कपूर (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि

बनाम

रवींद्र मोहन कपूर एवं अन्य

3 दिसंबर, 1986

[रंगनाथ मिश्रा और जी. एल. ओजा, न्यायाधिपतिगण]

विभाजन अधिनियम, 1893 - घर के विभाजन के लिए मुकदमा - समझौते के आधार पर एक पंचाट के आधार पर परिवार का निपटान - मुकदमे में वादी को कोई हिस्सा नहीं दिया गया - वादी संपत्ति में हिस्सेदारी का हकदार नहीं है।

चंद्रमोहन ने विवादित मकान ज्ञान चंद के पक्ष में दान कर दिया चंद, लेकिन बाद में उन्होंने उपहार रद्द करने के लिए वाद दायर किया। वाद को मध्यस्थ को संदर्भित किया गया जिसने अपना निर्णय दिया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और एक डिक्री का पालन किया गया। डिक्री के तहत चंद्रमोहन को अपने जीवन काल में भोग का अधिकार मिला। ज्ञान चंद और चंद्र मोहन के एक अन्य भाई मोहिंदर मोहन के बेटों को एक साथ एक-तिहाई हिस्सा मिला। शेष एक तिहाई हिस्सा आजीवन

ब्याज सहित चंद्रमोहन की बेटी को मिला और उसके बाद बिल्कुल उसके बेटे को।

बाद में महिंदर मोहन के तीन बेटों ने विवादित घर में अपने एक-तिहाई हिस्से पर विशेष कब्ज़ा करने के लिए मुकदमा दायर किया। अंत में, उच्च न्यायालय ने माना कि वे संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार नहीं थे।

चंद्र मोहन की विधवा और बेटे ने संपत्ति में दो-तिहाई हिस्सेदारी और उसके बंटवारे का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया। विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि पंचाट शून्य था और उपहार मान्य था और चूंकि इसके तहत, उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, इसलिए उन्हें विभाजन के लिए मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं था। हालाँकि, अपील में, उच्च न्यायालय ने पाया कि उनके पास एक तिहाई हिस्सा था और उस सीमा तक उनके दावे पर फैसला सुनाया।

ज्ञान चंद कपूर (प्रतिवादी संख्या 1) की अपील को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया:

1. उच्च न्यायालय का यह मानना गलत था कि वादीगण का संपत्ति में हिस्सा हिस्सा था। पहले मुकदमे में ही डिक्री समझौते पर आधारित पुरस्कार के आधार पर पारिवारिक समझौते की प्रकृति में थी। यह मानने का कोई औचित्य नहीं था कि उपहार जो घर की विषय वस्तु

के संबंध में शीर्षक का गठन करता था, एक दूसरे से अलग थे; विचारण न्यायालय का विचार भी उतना ही भ्रामक था कि समझौते, पुरस्कार और डिक्री के बावजूद, उपहार अभी भी वैध है क्योंकि इसे रद्द नहीं किया गया है। [400 ई- एफ]

2. स्वीकृत रूप से, उपहार के तहत या समझौते और पुरस्कार में वर्तमान वादी को कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, वादी संपत्ति में किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकते। [400 जी]

3. चंद्र मोहन की विधवा रमा देवी को संपत्ति के स्वामित्व के बिना विवाद वाले घर में अपने जीवन काल के दौरान रहने की अनुमति है। [401 बी-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार. सिविल अपील संख्या 558/1973

दिल्ली उच्च न्यायालय के आर.एफ.ए. नंबर 36-डी/1962 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 2.5.1972 से।

ए.बी. रोहतगी और बी.पी. माहेश्वरी, अपीलकर्ता की ओर से।

ओ.पी. वर्मा, प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय रंगनाथ मिश्रा, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। प्रमाण पत्र द्वारा यह अपील प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा है और एक घर के विभाजन और अन्य संबंधित राहत के मुकदमे में उच्च न्यायालय के उलट फैसले के खिलाफ निर्देशित है। विचारण न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर

दिया था लेकिन उच्च न्यायालय ने पाया कि वादी उनके द्वारा दावा किए गए दो-तिहाई हिस्से के मुकाबले एक तिहाई हिस्से के हकदार थे और इसके लिए एक डिक्री दे दी है। प्रतिवादी संख्या I, जो यह कहता है कि वादी को वाद घर में कोई दिलचस्पी नहीं है, ने अपीलीय डिक्री को चुनौती दी है।

स्वीकृत रूप से, विवाद वाला मकान चंद्रमोहन का था। 29.6.1937 को उन्होंने अपने भाई के बेटे ज्ञान चंद के पक्ष में इसका उपहार दिया, लेकिन 78.12.1937 को उपहार को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे को 31.5.1938 के एक आवेदन द्वारा वादी अधिवक्ता की मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था और मध्यस्थ ने पक्षकारो के बीच समझौते के आधार पर 20.6.1938 को अपना फैसला सुनाया, जिसे उन्होंने पारिवारिक समझौते के रूप में माना। उसी दिन न्यायालय द्वारा पंचाट स्वीकार कर लिया गया और एक डिक्री का पालन किया गया।

शासनादेश के तहत चन्द्रमोहन को अपने जीवन काल में भोग का अधिकार प्राप्त हुआ। ज्ञान चंद (प्रतिवादी नंबर 1) और चंद्र मोहन के एक अन्य भाई मोहिंदर मोहन के बेटों को एक साथ एक-तिहाई हिस्सा मिला। शेष एक-तिहाई हिस्सा आजीवन ब्याज सहित मृत पत्नी से दाता की बेटी तारावती को और उसके बाद, बिल्कुल उसके बेटे को दिया जाता था।

संपत्ति के संबंध में मुकदमेबाजी का दूसरा दौर जून 1953 में मोहिंदर मोहन के तीन बेटों द्वारा घर में अपने एक तिहाई हिस्से पर विशेष अधिकार और हिसाब-किताब की मांग के मुकदमे के साथ शुरू हुआ। उतार चढाव भरे करियर के बाद, इस मुकदमे को आर.एस.ए. नंबर 61-डी / 1958 में उच्च न्यायालय के फैसले से अंतिम मुहर मिली। उच्च न्यायालय ने माना कि तीनों वादी संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार नहीं थे।

मुकदमे के दूसरे दौर के निपटारे के तुरंत बाद, रमा देवी और उनके बेटे रवीन्द्र ने क्रमशः चंद्र-मोहन की विधवा और बेटे होने का दावा करते हुए संपत्ति में दो-तिहाई हिस्सेदारी और अन्य सहायक राहतों के साथ उसके विभाजन का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया। विचारण कोर्ट ने यह पाते हुए मुकदमा खारिज कर दिया:

1. रमा देवी चंद्र मोहन की पत्नी थीं और रवीन्द्र उनके बेटे हैं;

2. मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में उच्च न्यायालय के फैसले ने वर्तमान दावे पर रोक नहीं लगाई;

3. पंचाट शून्य था और उपहार मान्य था और चूंकि इसके तहत वादी को कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, इसलिए उन्हें विभाजन के लिए मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं था।

उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय से सहमत नहीं था कि पंचाट गलत था और उपहार मान्य था। इसमें पाया गया कि वादी के पास एक

तिहाई हिस्सा था और उस सीमा तक दावे पर फैसला सुनाया गया। प्रतिवादी संख्या । की यह अपील इस पलटने वाले डिक्री के विरुद्ध है।

हमारी राय में, उच्च न्यायालय का यह मानना गलत था कि वादी का संपत्ति में हिस्सा था। पहले मुकदमे में ही डिक्री समझौते पर आधारित पुरस्कार के आधार पर पारिवारिक समझौते की प्रकृति में थी। यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि उपहार जो उसके विषय-वस्तु के संबंध में शीर्षक का गठन करता है, अर्थात्, घर, एक दूसरे से अलग थे, विचारण न्यायालय का यह विचार भी उतना ही भ्रामक था कि समझौते के बावजूद, पुरस्कार और डिक्री के अनुसार, उपहार अभी भी वैध है क्योंकि इसे रद्द नहीं किया गया है: बेशक उपहार के तहत या समझौते और पुरस्कार में वर्तमान वादी को कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, वादी संपत्ति में किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकते। वादी के पक्ष में एक तिहाई हिस्सा देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क न तो कानून में और न ही तथ्यों पर मान्य है। इस स्तर पर दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के फैसले की सत्यता की जांच करना उचित नहीं है। उस फैसले से महिंदर मोहन ने संपत्ति का मालिकाना हक खो दिया था।

अपील की सुनवाई के दौरान वादी-प्रतिवादियों की ओर से एक हलफनामा दाखिल कर यह बताया गया कि विजय कुमार तारावती का बेटा नहीं है। हलफनामा जो तथ्य के प्रश्न को फिर से खोलने का प्रयास करता

है वह इस स्तर पर अपनाया नहीं जा सकता। वादी के पास कोई स्वामित्व नहीं है और इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वे घर में एक तिहाई हिस्सेदारी के हकदार नहीं होंगे। अपील स्वीकार की जाती है और वादी का मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए। हम उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं और विचारण न्यायालय के फैसले को इस निर्देश के साथ बहाल करते हैं कि पक्षकार पूरी लागत स्वयं वहन करेंगे।

रमा देवी चंद्र मोहन की विधवा और रवींद्र मोहन पुत्र हैं। सबूतों से पता चलता है कि ये दोनों इसी घर में रह रहे थे। हमारा मानना है कि यह उचित है कि रमा देवी को उनके जीवनकाल के दौरान संपत्ति के स्वामित्व के बिना इस घर में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि आज से छह महीने के भीतर रमा देवी के लिए आवासीय हिस्सा सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं बनाया जाता है, तो वह अपने जीवन काल के दौरान अपने रहने के लिए घर का एक उचित हिस्सा आवंटित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष आवेदन कर सकती हैं, किसी भी प्रकार से अलगाव के अधिकार के बिना।

ए.पी.जे.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।